



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1991/चैत्र 6, 1913

No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1991/CHAITRA 6, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1991

सा. का. नि. 192 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“स. आ. 146 ”

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1991

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1991 है।

2. संविधान, खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3 (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उद्देश्य के अनुसार 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में :—

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के सामने राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (11) में विनिर्दिष्ट राशियां जो उन स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के विकास संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और ‘विशेष समस्थानों’ से संबंधित कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजा की प्रकृति के व्यय के लिए है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

पन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रकृति संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर व्यय की जाएंगी।

सारणी

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए									
	पुलिस	शिक्षा	जेल	जनजाति	स्वास्थ्य	न्यायिक	जिला और राजस्व	खजाना और लेखा	प्रशिक्षण	विशेष समस्याएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(रुपए लाखों में)										
घाट्य प्रदेश	2.46	162.02	14.82	16.35	110.49	56.83	11.94	2.93	17.21	831.58
गोवा	5.41	3.45	—	—	—	1.52	8.09	1.88	—	11.25
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	646.11
हिमाचल प्रदेश	—	5.19	0.14	0.20	0.81	0.41	2.55	0.49	1.78	46.02
केरल	10.36	—	5.22	1.13	—	9.86	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	22.09	—	25.10	81.60	12.71	—	11.27	0.88	3.53	290.02
महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—	770.51
मणिपुर	11.83	82.5	—	9.85	1.99	1.58	9.46	—	2.79	9.30
मेघालय	22.24	—	—	—	3.87	—	—	—	2.20	—
मिजोरम	25.00	3.75	—	15.65	7.06	1.00	—	—	—	87.50
नागालैण्ड	—	—	107.85	—	2.43	1.65	7.31	2.43	4.70	375.00
उड़ीसा	93.07	—	—	17.55	—	1.12	15.26	1.16	—	—
पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1442.38
राजस्थान	103.06	—	97.59	—	17.09	52.50	48.74	2.46	—	158.73
सिक्किम	3.11	—	0.28	—	—	—	—	—	0.20	17.71
त्रिपुरा	43.07	54.17	1.00	1.20	3.70	—	1.78	—	1.16	—
उत्तर प्रदेश	181.22	—	2.11	0.45	52.86	70.58	40.87	17.70	27.72	3848.28
कर्णैली केरान	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1225.00

ध्यान दें: यह और कि किसी प्रशासन के संघ में ऊपर निर्दिष्ट अनुदान की रकम, 1 अप्रैल, 1991 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान, जैसा कि वर्ष के लेखा में प्रकट किया गया है, वे प्रशासन संबंधी अनुदानित कार्यक्रमों या कार्यक्रमों में उपगत वास्तविक व्यय के विवरण समायोजन के अधीन हैं।

(ख) नीचे दी गई सारणी के संघ (1) में निर्दिष्ट प्रदेश राज्य के समस्त राजस्वों में सहायता प्रदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से (11) में निर्दिष्ट राशियाँ, जो उक्त संघों में वर्णित स्तर को ऊंचा उठाने और "विशेष समस्याएँ" के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों पर 1 अप्रैल, 1990 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष में उपगत राजस्व और पंजी की प्रकृति के व्यय के लिए हैं, भारत की संविधान विधि पर भारत होगी:—

सारणी

राज्य	निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए									
	पुलिस	शिक्षा	जेल	जनजाति	स्वास्थ्य	न्यायिक	जिला और राजस्व	खजाना और लेखा	प्रशिक्षण	विशेष समस्याएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(रुपए लाखों में)										
अरुणाचल प्रदेश	77.88	7.22	—	—	28.99	—	—	3.28	—	—
असम	—	—	—	91.06	1.57	21.53	4.53	13.05	—	100.00
गोवा	—	8.61	—	—	10.82	10.53	2.56	—	—	—
केरल	49.38	—	11.91	1.44	4.25	23.20	5.80	0.76	—	—
मध्य प्रदेश	59.12	—	659.64	122.05	5.41	0.21	7.52	0.60	—	3.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भेषालय	31.81	23.09	—	—	—	2.60	1.24	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	4.80	—	—
नागालैण्ड	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—
उड़ीसा	—	221.80	—	54.58	0.21	—	1.44	—	—	—
राजस्थान	12.50	—	16.59	7.83	12.52	1.86	7.01	1.00	3.94	56.99
सिक्किम	0.21	—	—	1.09	0.76	—	(-) 0.34	—	—	—
त्रिपुरा	20.91	2.85	—	1.50	2.57	—	0.39	0.98	9.29	—
उत्तर प्रदेश	90.48	—	114.90	1.50	21.84	4.15	41.60	17.49	—	—
पश्चिम बंगाल	609.58	284.73	108.15	99.26	46.66	12.53	7.11	10.55	20.00	—

परन्तु यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उन वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के सामने उपर विनिर्दिष्ट अनुदान को एक से कम है, तो इस प्रकार अनिवार्य संवत् की गई रकम ऐसी किसी राशि या राशियों के विद्युत समायोजित की जाएगी, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संवेष्ट हो जाए।

(2) 1 अप्रैल, 1990 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उपपैरा (1) के खंड (ग) और (ख) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियाँ, संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 अधिनियम, 1990 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के प्रतिरिक्त होंगी।

आर. वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[क्र. सं. 19 (2)/91- एल.-1]

के. एल. मोहनपुरिया, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1991

G.S.R. 192(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 146"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1991

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1991.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1990, as grants-in-aid of the revenues of—
- (a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature on programmes for upgradation of standards and "Special Problems" relating to the administration of the sectors and services mentioned in these columns :—

TABLE

For upgradation of standards relating to

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manipur	11.83	82.55	..	9.85	1.99	1.58	9.46	..	2.79	9.30
Meghalaya	22.34	3.67	2.20	..
Mizoram	25.00	3.75	..	15.65	7.06	1.00	87.50
Nagaland	107.85	..	2.43	1.65	7.31	2.43	4.70	375.00
Orissa	93.07	17.55	..	1.17	15.26	1.16
Punjab	1442.38
Rajasthan	103.06	..	97.59	..	17.09	52.50	48.74	2.46	..	158.73
Sikkim	3.11	..	0.28	0.20	17.71
Tripura	43.07	54.17	1.00	1.20	3.70	..	1.78	..	1.16	..
Uttar Pradesh	181.32	..	2.11	0.45	52.86	70.58	40.87	17.70	27.72	848.28
West Bengal	1225.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government :

Provided further that the amount of grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 1991 against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as revealed in the accounts of that year;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (11) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes approved by the Central Government for upgradation of standards and "Special Problems" mentioned in those columns, incurred in the financial year commencing on the 1st day of April, 1990 :-

TABLE

State	For upgradation of standards relating to									
	Police	Education	Jail	Tribal	Health	Judicial	District and Revenue	Treasury and Accounts	Training	Special Problems
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Rupees in lakhs)										
Arunachal Pradesh	77.88	7.22	28.99	8.28
Assam	91.06	1.57	21.53	4.53	13.05	..	100.00
Goa	..	8.61	10.82	10.53	2.56
Kerala	49.38	..	11.91	1.44	4.25	23.20	5.80	0.76
Madhya Pradesh	59.12	..	659.64	122.05	5.41	0.21	7.52	0.60	..	3.48
Meghalaya	31.81	23.09	2.60	1.24
Mizoram	4.80
Nagaland	0.07
Orissa	..	221.80	..	54.58	0.25	..	1.44
Rajasthan	13.50	..	16.29	7.83	12.52	1.86	7.01	1.00	3.94	56.99
Sikkim	0.21	1.09	0.76	..	(—)0.34
Tripura	20.91	2.85	..	1.50	3.57	..	0.39	0.98	9.29	..
Uttar Pradesh	90.48	..	114.90	1.50	21.84	4.15	41.60	17.29
West Bengal	609.58	284.76	108.15	99.26	46.66	12.53	7.11	10.53	20.00	..

Provided that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1) to any State in the financial year commencing on the 1st day of April, 1990 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1990.

R. VENKATARAMAN,
President

[F. 19(2)/91-L.I.]

K.L. MOHANPURIA, Addl. Secy.